



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2015/चैत्र 18, 1937

No. 84]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2015/CHAITRA 18, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2015

जांच शुरूआत अधिसूचना

विषय : चीन और रूस में उद्धवित या वहां से निर्यातित 'मिथायलीन क्लोराइड' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत

फा.सं. 14/33/2014-डीजीएडी – मैसर्स केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड और मैसर्स गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें एतदपश्चात "याचिकाकर्ता कंपनियां" या "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र चीन जन.गण. और रूस (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित मिथायलीन क्लोराइड, जिसे "डायक्लोरोमीथेन" या "मिथायलीन क्लोराइड" के नाम से भी जाना जाता है, (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु या एमडीसी या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध करते हुए दायर किया है।

2. और यतः, प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और इसलिए प्राधिकारी, एतद्वारा कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी राशि की सिफारिश करने, जो यदि उद्वृत्त की गई, तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग का परिणामी क्षति की जांच करने के लिए एतद्वारा एक जांच की शुरूआत करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान याचिका और प्रस्तावित जांच में विचाराधीन उत्पाद "मिथायलीन क्लोराइड" है जिसे "डायक्लोरोमीथेन" और "मिथायलीन डायक्लोराइड" (एमडीसी) के नाम से भी जाना जाता है। मिथायलीन क्लोराइड एक आर्गेनिक यौगिक है जिसका मालिक्यूलर फार्मूला सीएच₂सीएल₂ है। यह एक रंगहीन द्रव होता है, जिसकी मनभावन ईथर जैसी सुगंध होती है और इसका प्रयोग प्रमुखतः विलायक के रूप में किया जाता है। यह प्रयोग की अधिकांश परिस्थितियों के अंतर्गत अनिवार्यतः गैर-ज्वलनशील होता है। तथापि, अधिक गरम किए जाने पर यह ज्वलनशील भी हो सकता है। मिथायलीन क्लोराइड को उच्च ताप पर अपघटित करके विषाक्त गैसों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कई विलायकों में पूर्णतः घुलनशील है। एमडीसी एक विलायक है और इसका प्रयोग पालीकार्बोनेट और फिनोलिक रेजिन्स, रेयान यार्न, फार्मास्युटिकल्स, कृषि और सुगंधित पदार्थों का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। यह खाद्य वसा, कोकोआ, मक्खन और

सतों के लिए निष्कर्षणीय के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिथायलीन क्लोराइड का उत्पादन करने के लिए दो प्रविधियां हैं – मिथेन रूट और मेथनल रूट। इन दोनों रूटों द्वारा उत्पादित उत्पाद के अनिवार्यतः समान तकनीकी विनिर्देशन होते हैं। मिथायलीन क्लोराइड को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 (आर्गेनिक रसायन) के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक 29031200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक हैं और यह किसी भी रूप में प्रस्तावित जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

4. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु दोनों समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मिथायलीन क्लोराइड और संबद्ध देशों से आयातित मिथायलीन क्लोराइड दोनों अनिवार्य उत्पाद अभिलक्षणों में समान हैं जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रकार्य, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में एक समान है; दोनों ही प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्तागण इन दोनों का अंतरपरिवर्तनीय रूप से प्रयोग करते हैं। आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में माना जाता है।

घरेलू उद्योग

5. यह आवेदनपत्र मैसर्स केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड और मैसर्स गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के दो अन्य घरेलू उत्पादक भी हैं अर्थात् मैसर्स जीएसीएल और एसआरएफ लिमिटेड। यह नोट किया जाता है कि आवेदकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन है और याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारत में उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन में एक बड़ा अनुपात बनता है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी आवेदक ने इस विचाराधीन उत्पाद का न तो आयात किया है और न ही उनका संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से कोई संबंध है। अतः यह निर्धारित किया जाता है कि यह आवेदन पत्र घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर से दायर की गई है और यह आवेदन पत्र नियमावली के अंतर्गत आधार की जरूरत को संतुष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, आवेदकगण पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार "घरेलू उद्योग" है।

अंतर्ग्रस्त देश

6. इस समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण. और रूस है।

सामान्य मूल्य

7. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के उपाबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदकों ने यह प्रस्तुत किया है कि वे किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के किसी उत्पादक से ऐसी सूचना अवाप्त करने में सक्षम नहीं रहे हैं और इसलिए, चीन जन.गण. के सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत, विधिवत समायोजित के आधार पर किया गया है।

8. जहां तक रूस के लिए सामान्य मूल्य का संबंध है आवेदकों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि संबद्ध देशों की घरेलू उद्योग बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक यह सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे। इसलिए आवेदकों ने सभी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य की रचना भारत में उत्पादन लागत का विधिवत समायोजन करके किया गया है।

निर्यात कीमत

9. आवेदकों ने दिसम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध सौदावार आंकड़ों के आधार पर और जनवरी, 2013 से अब तक की अवधि के लिए टिप्स मुंबई से सौदावार आंकड़ों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का दावा भारत में आयातों की मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, बैंक प्रभार, वैट अंतर (केवल चीन के लिए) के आधार पर कीमत समायोजन किया है।

पाटन मार्जिन

10. आवेदकों ने इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से पर्याप्ततः उच्चतर है, जिससे, प्रथमदृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों में उद्धावित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है जो पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने के लिए न्यायोचित ठहरता है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. आवेदकों ने यह दावा किया है कि उन्हें वास्तविक क्षति हुई है और उन्होंने संबद्ध देशों से कथित पाटन के परिणामस्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और नकद लाभ आदि में गिरावट तथा आयातों में समग्र रूप से वृद्धि के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

12. आवेदकों ने विपरीत कीमत प्रभाव का दावा भी किया है जैसाकि कीमत निग्रहण और कीमत अधोरदन से स्पष्ट हो रहा है। प्राधिकारी विचार करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा आवेदकों की "क्षति" कारित किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे पाटनरोधी जांच प्रारंभ करना न्यायोचित ठहरता है।

जांच की अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2013 से सितम्बर, 2014 (12 माह) हैं। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014 तथा जांच की अवधि को शामिल किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

14. सम्बद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों तथा उनकी सरकार को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी अधोलिखित निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने हेतु अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित समय-सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग में इस जांच से संगत जानकारी का प्रस्तुतिकरण कर सकता है। यह सूचना/ प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित को प्रस्तुत की जा सकती है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार

चौथा तल, जीवन तारा भवन, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित निर्धारित समय-सीमा के अंदर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत जानकारी का प्रस्तुतिकरण कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका अगोपनीय पाठ भी उपलब्ध कराए।

समय-सीमा

16. वर्तमान जांच से संबंधित किसी भी सूचना को लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस जांच शुरूआत अधिसूचना के संप्रेषण की तारीख से चालीस (40) दिनों के से अनधिक समय में पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

17. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर इस जांच शुरूआत अधिसूचना के संप्रेषण की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए। गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. प्रश्नावली प्रत्युत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रस्तुति (इससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षों से इसे दो पृथक सेटों में यदि "गोपनीयता" का इसके किसी भाग पर दावा किया जाता है, फाइल किया जाना अपेक्षित है:-

(क) एक सेट गोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो, और

(ख) एक अन्य सेट अगोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो।

19. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" की प्रस्तुति को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" रूप में स्पष्टतः चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्हांकन के बिना की गई किसी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय रूप में समझा जाएगा और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि ऐसी प्रस्तुति का निरीक्षण करने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षकारों को अनुमति प्रदान करें। दोनों संस्करणों की साँफ्ट कापी भी प्रत्येक के पांच (5) सेटों में हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

20. गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी सूचनाएं समाविष्ट होंगी जो प्रकृति में गोपनीय हों और/अथवा अन्य सूचना जिसके बारे में ऐसी सूचना की आपूर्ति करने वाला गोपनीयता के रूप में दावा करता हो। सूचना, जिसकी प्रकृति में गोपनीयता के रूप में दावा किया जाता है अथवा सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, के लिए, सूचना आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सूचना कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है, के साथ एक उचित कारण विवरण दिया जाना अपेक्षित है।

21. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए (यदि अनुक्रमणिका सम्भव न हो) और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

22. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

24. प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. प्राटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं कराता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी उनको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

DEPARTMENT OF COMMERCE

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2015

Sub: - Initiation of Anti Dumping investigation on imports of “Methylene Chloride” originating in or exported from China PR and Russia.

No.14/33/2014-DGAD – M/s Chemplast Sanmar Ltd and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd (hereinafter referred to as ‘petitioner companies’ or “the applicants”) have filed an application before the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein after referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the AD Rules or the Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning alleged dumping of Methylene Chloride, also known as “Dichloromethane” or “Methylene Dichloride” (MDC) (hereinafter referred to as the subject goods or MDC or the Product Under Consideration) originating in or exported from China PR and Russia (hereinafter referred to as the subject countries).

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exists, and the Authority, therefore, hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequential injury to the domestic industry in terms of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Product under consideration

3. The product under consideration in the present petition and the proposed investigation is “Methylene Chloride”, also known as “Dichloromethane” or “Methylene Dichloride” (MDC). Methylene Chloride is an organic compound with molecular formula CH₂Cl₂. It is a colorless liquid with sweetish ether-like odor, and is used as a solvent, predominantly. It is essentially non- flammable under most conditions of use. However, it can burn if strongly heated. Methylene Chloride may decompose at high temperatures forming toxic gases. It is completely miscible with a variety of solvents. MDC is a solvent and is used in the manufacturing of polycarbonate and phenolic resins, rayon yarn, pharmaceuticals, agro and fragrance. It is also used as an extractant for edible fats, cocoa, butter and essences. There are two technologies for production of Methylene Chloride - Methane route and Methanol route. The product produced through the two routes has essentially similar technical specifications. Methylene Chloride is classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act under customs subheading 29031200. The Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the proposed investigation.

Like Article

4. The applicant has claimed that the subject goods, which are exported from the subject countries into India are identical to the goods produced by the domestic industry. Methylene Chloride produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry

5. The application has been filed by M/s Chemplast Sanmar Ltd. and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. It is noted that there are two other domestic producers of the subject goods, i.e., M/s. GACL and SRF Limited. It is noted that the applicants account for more than 50% of the total Indian production and production by the petitioners constitute a major proportion in the total production of the like product produced in India. It is also noted that none of applicants has imported the product under consideration, nor they are related to any exporter of the subject goods in the subject countries or importer of the subject goods in India. It is thus determined that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of 'standing' under the Rules. Further, the applicants constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

Countries involved

6. The countries involved in the present investigation are China PR and Russia.

Normal Value

7. The applicants have claimed that China PR should be treated as Non-Market Economy and, therefore, the normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annex-I of the Rules. Applicants have submitted that they have not been able to procure such information from a producer in the market economy third country and have, therefore, determined the Normal Value in China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

8. As regards the normal value for Russia, the applicants have submitted that efforts were made to get information/evidence of price of the subject goods in the domestic market of the subject countries. However, applicants were not able to get such information. The applicants have, therefore, constructed normal value for all subject countries on the basis of cost of production in India duly adjusted.

Export Price

9. The applicants have claimed export price for product under consideration based on the transaction wise data available from DGCI&S for the period upto Dec 2012, and transaction wise data for the period from January, 2013 from TIPS, Mumbai, to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses, bank charges, VAT difference (only for China).

Dumping Margin

10. The applicants have provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

Injury and Causal Link

11. The applicants have claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping from the subject countries in terms of increase in imports in absolute terms and deterioration in profits, return on capital employed and cash profit etc.

12. The applicants have also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression and price undercutting. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicants caused by dumped imports of the subject goods from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

13. The period of investigation (POI) is October 2013 to September 2014 (12 months) for the purpose of the present investigation. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2011 - March 2012, April 2012-March 2013, April 2013-March 2014 and the POI.

Submission of information

14. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Government of India

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi-110001

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

16. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the communication of initiation of this investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the communication of initiation of this investigation. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

18. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

19. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

20. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

24. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

25. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

26. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority